बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 97 ● नई दिल्ली ● शनिवार 24 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई टली, तीसरे जज ने भी खुद को किया अलग

नई दिल्ली। चीनी वीजा घोटाला मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट के एक और न्यायमूर्ति ने खुद को अलग कर लिया है। शुक्रवार को मामला जब न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ के समक्ष आया तो उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। अब मामले की सुनवाई अन्य पीठ के समक्ष 28 जनवरी को होगी। इससे पहले न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी के सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद मामले को न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश और गरज के साथ बदला मौसम, कड़ाके की ठंड की वापसी, अगले कुछ घंटों के लिए अलर्ट जारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में शुक्रवार सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। कई इलाकों में मध्यम बारिश के साथ गरज और तेज हवाएं चलीं, जिससे सुबह की शुरुआत ठिठुरन के साथ हुई। मौसम विभाग ने सुबह 7:30 बजे चेतावनी जारी करते हुए बताया कि अगले दो से तीन घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली-एनसीआर में यह बदलाव देखा जा रहा है। बारिश के बाद दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट की संभावना जताई गई है। सुबह से ही 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे कनकनी बढ़ गई है। दिल्ली-एनसीआर और पंजाब और हरियाणा के कई आस-पास के इलाकों के लिए आंधी-तूफान और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, जिससे शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। दोपहर में और बारिश होने की संभावना है, साथ ही आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी। दिल्ली में गुरुवार को पिछले सात सालों में जनवरी का सबसे गर्म दिन रहा, जब अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालाँकि, मौसम विभाग ने कहा कि शुक्रवार को अधिकतम

तापमान में तेज़ी से गिरावट आने और लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस बीच, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में गुरुवार की तुलना में मामूली सुधार हुआ, लेकिन यह बहुत खराब श्रेणी में बनी रही, एक्यूआर 302 रहा। नोएडा की स्थिति बेहतर रही, जहां एक्यूआर 293 के साथ खराब श्रेणी में रहा, जबकि गुरुग्राम भी एक्यूआर 272 के साथ खराब श्रेणी में रहा। एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम के एयर क्वालिटी पूर्वानुमानों से पता चलता है कि 23 और 24 जनवरी को हवा की गुणवत्ता मध्यम रहने की संभावना है, जिसके बाद 25 जनवरी को यह खराब श्रेणी में आ जाएगी। इस बीच, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने समग्र हवा की गुणवत्ता में सुधार का हवाला देते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज III को रद्द कर दिया है। हालाँकि, स्टेज I और II के तहत उपाय लागू रहेंगे। गुरुवार सुबह जम्मू शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, जिससे ठंड बढ़ गई क्योंकि पूरे क्षेत्र में शीतलहर की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग ने लंबे समय तक सूखे के बाद उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है, और कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बर्फबारी तेज़ हो गई है। आईएमडी के अनुसार, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग और चमोली में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं की संभावना के कारण बाकी ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बर्फबारी के इस नए दौर से सूखे की स्थिति से बहुत ज़रूरी राहत मिलने की उम्मीद है और इससे पहाड़ी राय में जंगल की आग का खतरा कम करने में भी मदद मिल सकती है।

प्रधानमंत्री इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने में सबसे माहिर, कांग्रेस ने क्यों लगाए ये आरोप?

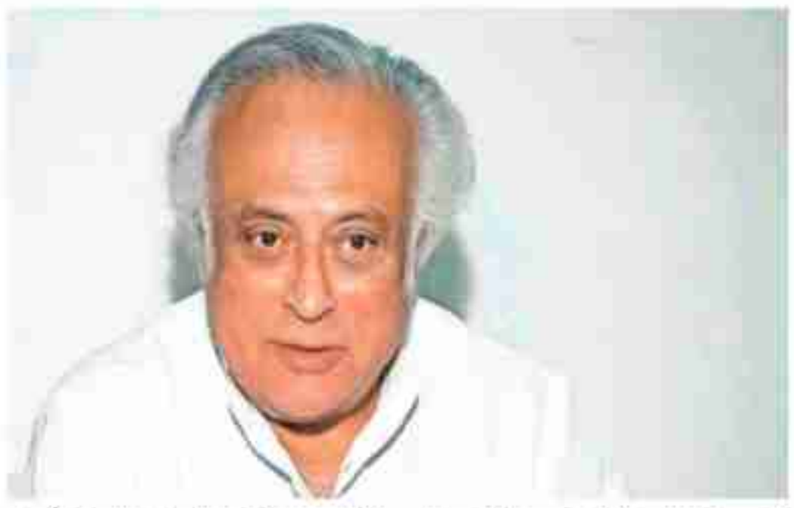

नई दिल्ली । कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुक्रवार को तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने में सबसे माहिर हैं। कांग्रेस ने ये भी कहा कि राष्ट्रगान के इतिहास से भी छेड़छाड़ की कोशिश की गई और बीते महीने संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान रवींद्रनाथ टैगोर का भी अपमान करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस संचार प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में आरोप लगाया कि पीएम मोदी व्यवस्थागत तरीके से महात्मा गांधी की यादों और विरासत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम रमेश ने पोस्ट में लिखा, बीते महीने संसद में राष्ट्रगीत पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी और उनके सहयोगी बेनकाब हो गए। राष्ट्रगान के इतिहास से भी छेड़छाड़ की कोशिश की गई और इस दौरान गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का भी अपमान का प्रयास किया गया। आज 23 जनवरी 2026 के दिन देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मना रहा है, जिन्होंने 1937 में वंदे मातरम की पंक्तियों को लेकर हुए विवाद को सुलझाने में मुख्य भूमिका निभाई, जिसका पीएम मोदी ने जानबूझकर जिक्र नहीं किया। जयराम रमेश ने लिखा नेताजी सुभाषचंद्र बोस के परपोते और इतिहासकार सुगत बोस ने लिखा कि नेताजी ने 2 नवंबर 1942 को बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया था और उस दौरान उन्होंने राष्ट्रगान के दौरान पर जन गण मन गाया था। नेताजी ने ही 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से प्रसारित संदेश में पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अब प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की यादों और विरासत को व्यवस्थागत तरीके से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका ताजा उदाहरण मनरेगा कानून वापस लेना है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने में सबसे माहिर हैं। बीते माह संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई।

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बंगाल में चुनाव होने के चलते वंदे मातरम पर विशेष चर्चा की जा रही है। कांग्रेस ने भाजपा पर वंदे मातरम के नाम पर राजनीति करने और इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश करने जैसे आरोप लगाए। इसके जवाब में सत्तापक्ष ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।

दिल्ली में 1 फरवरी को होगी सरकारी छुट्टी? कांग्रेस ने रेखा गुप्ता की सरकार ने की मांग

नई दिल्ली । दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती को लेकर दिल्ली सरकार से बड़ा फैसला लेने की मांग की है. उन्होंने कहा कि गुरु रविदास के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए 1 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश के साथ ड्राई डे घोषित किया जाना चाहिए. इस मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीधा दबाव बनाया है. देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार को संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती 1 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश और ड्राई डे घोषित करना चाहिए. उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल से प्रस्ताव तुरंत पास कराकर अधिसूचना जारी करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि आस्था और सम्मान से जुड़ा मामला है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दलित समाज की भावनाओं के साथ लगातार राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा कि साल 2025 में विधानसभा चुनाव के बाद दलित समाज की सहानुभूति पाने के लिए बीजेपी के समर्थन से उपराज्यपाल ने 12 फरवरी 2025 को रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था. उस दिन सरकारी कार्यालय, स्कूल और स्थानीय निकाय बंद रहे, लेकिन ड्राई डे की स्पष्ट घोषणा नहीं हुई. यादव के मुताबिक, यह भाजपा समर्थित सोच को दिखाता है. देवेंद्र यादव ने 10 अगस्त 2019 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर तुगलकाबाद स्थित संत रविदास रविदास मंदिर को ध्वस्त किया. उन्होंने इसे दलित समाज की धार्मिक आस्था पर सीधा प्रहार बताया और कहा कि यह मंदिर समुदाय के लिए ऐतिहासिक और पवित्र रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा सभी धर्मों और जातियों का समान सम्मान करती रही है. उनके अनुसार, कांग्रेस के प्रयासों से ही दलित समाज को बराबरी का दर्जा मिला और आज इस वर्ग के लोग देश-दुनिया में ऊंचे पदों पर हैं. इसके उलट, भाजपा पर उन्होंने दलित समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखने का आरोप लगाया. देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में रविदासिया समुदाय की संख्या काफी अधिक है. ऐसे में गुरु रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश और ड्राई डे घोषित किया जाना पूरी तरह न्यायसंगत है. उन्होंने कहा कि जैसे अन्य धार्मिक त्योहारों पर संबंधित समुदाय की आस्था के सम्मान में ड्राई डे घोषित होता है, वैसे ही रविदास जयंती भी उसी सम्मान की हकदार है.

दिल्ली के कब सुधरेंगे हालात? बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर रोक रहे रास्ता; हादसों का भी बना रहता है खतरा

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रमुख खड़कों पर 25 बिजली के खंभे और कई ट्रांसफार्मर आम जनता का रास्ता रोक रहे हैं, ये केवल एक इलाके में नहीं हैं, बल्कि दिल्ली भर में हैं और जनता इनसे परेशान है। कहीं ये बीच सड़क पर हैं तो कहीं ये सड़क के किनारे हैं और सड़कों को संकरा कर दे रहे हैं। कई जगह बिजली के खंभे ऐसे स्थानों पर हैं, जहां लोगों को आवागमन में दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। मगर इन्हें हटाने की गति बहुत धीमी है। वहीं, इसे लेकर लोक निर्माण विभाग ने इन्हें हटाने के लिए अलग-अलग समय में बिजली वितरण कंपनियों के साथ मौके का सर्वेक्षण किया है, इन्हें हटाने पर हो रही देरी पर बिजली विभाग को पत्र लिखे हैं। मगर उपयुक्त जगह उपलब्ध न होने और सरकारी हीलाहवाली के चलते ये अभी तक नहीं हट पाए हैं। बिजली के खंभों को लेकर जहां यादा समस्या आ रही है कुल 25 बाधाएं हैं। उनमें बचे हुए 25 में से 15 छतरपुर के एसएसएन मार्ग पर हैं, दो अरबिंदो मार्ग पर और तीन नजफगढ़ मुख्य सड़क पर हैं। वहीं, नौ ऐसे खंभों/ट्रांसफार्मरों को स्थानांतरित भी कर किया गया है, इनमें लक्ष्मी नगर में पुस्ता रोड, वजीराबाद पर पुस्ता रोड, दिलशाद गार्डन में जेएंडके पाकेट रोड और मयूर विहार फेज-1 में पीपीजी रोड शामिल हैं। ये सभी सड़कें पीडब्ल्यूडी के अधीन आती हैं, जो दिल्ली की 60 फीट चौड़ी या उससे अधिक सड़कों का रखरखाव करता है।

नजफगढ़ के लिए, पीडब्ल्यूडी को मौके पर सर्वेक्षण के लिए एक पत्र लिखा गया है। अरबिंदो मार्ग पर निरीक्षण पहले ही पूरा हो चुका था, हालांकि, ट्रांसफार्मरों को स्थानांतरित करने के लिए कोई जगह नहीं पहचानी जा सकी है। इसी तरह एसएसएन मार्ग पर मौके पर निरीक्षण पूरा हो गया था, लेकिन अभी तक कोई वैकल्पिक जगह नहीं मिली है। पूर्वी दिल्ली में, बाधाओं को स्थानांतरित करने के लिए वैकल्पिक जगह की कमी एक मुद्दा है। पीडब्ल्यूडी अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं करा पाया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2019-20 में पूर्वी बाबरपुर में यातायात में बाधा बन रहे एक ट्रांसफार्मर को चिह्नित किया था, जिसे अभी तक स्थानांतरित किया जाना बाकी है। बता दें कि डिस्कॉम बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) के पास 7,596 ट्रांसफार्मर हैं। बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) के पास 2,122 ट्रांसफार्मर हैं। वहीं टाटा पावर डीडीएल के अधिकार क्षेत्र में 24,986 ट्रांसफार्मर हैं।

किराड़ी जलभराव विवाद पर भिड़े सांसद- आप विधायक, तीखे सवालों के बीच जमकर हुई नारेबाजी

बाहरी दिल्ली।

किराड़ी की शर्मा कालोनी के हालात का जायजा लेने पहुंचे भाजपा सांसद योगेंद्र चांदोलिया व विधायक अनिल झा के बीच तीखी नोंक-झोंक देखने को मिली। शुक्रवार सुबह लगभग 12 बजे स्थानीय सांसद योगेंद्र चांदोलिया जिले कई अधिकारियों सहित शर्मा कालोनी में हालतों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इसी दौरान दौरा करते हुए किराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा भी अपने समर्थकों के साथ भी दौरा कर रहे थे।

हनुमान मंदिर के पास सांसद और विधायक का आमना-सामना हो गया। विधायक ने सांसद से शर्मा कालोनी में जलभराव को लेकर सवाल किया तो दोनों नेताओं से तीखी बहस होने लगी। इस बीच दोनों नेताओं के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। लगभग 20 मिनट तक हंगामे की स्थिति रही। पुलिस ने समर्थकों को शांत कराया। शर्मा कालोनी के लोगों से बातचीत के दौरान सांसद ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया।

सोये सिस्टम का खामियाजा

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की ज्यादातर सोसायटी में मिलने वाले फ्लैट्स की कीमत करोड़ों रुपये में है। मेगा सिटी की तर्ज पर बसाया गया यह शहर आज भी बदहाली की मार झेल रहा है। बारिश में इस शहर की सड़कों पर पानी भर जाता है तो अब बिना बारिश के ही एक युवा इंजीनियर 'सिस्टम की गलती' से भरे पानी में डूबकर अपनी जान गंवा बैठा। आलम ऐसा था कि पुलिस को पता था, प्रशासन को पता था, आपदा में मदद पहुंचाने के लिए बने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी पता था लेकिन सड़क से चंद फीट दूर भरे पानी में एक युवा डूब गया और सिस्टम अपनी ही चाल चलता रह गया। नोएडा की घटना से दिल्ली-एनसीआर में प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठे हैं। खुले नाले, खराब ड्रेनेज और सड़क सुरक्षा की अनदेखी से हाल के वर्षों में जानलेवा हादसे हुए हैं। दिल्ली में जनवरी 2024 से दिसम्बर 2025 के बीच 80 मौतें केवल डूबने से हुई हैं लेकिन इस घटना ने सोये सिस्टम का खामियाजा इंजीनियर को भुगतना पड़ा। सिस्टम की इस कछुआ चाल का नतीजा यह है कि एक पिता ने अपना बेटा खो दिया है और वह न्याय की गुहार लगा रहा है। न्याय के नाम पर कुछ अफसरों के तबादले हो गए, कुछ को हटा दिया गया और लीपापोती शुरू हो गई। पानी से भरे गड्ढे में डूब रहे युवक को बचाने के लिए डिलीवरी ब्वॉय मोनिंदर ने तो जान की बाजी लगा दी लेकिन मौके पर मौजूद प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी जगह 15 दिन पहले भी हादसा हुआ था, मगर अथॉरिटी ने कोई सबक नहीं लिया। अब सरकार ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को हटाने और घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। किसी मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकारी तंत्र की नींद जरूर खुलती है लेकिन तब तक किसी निर्दोष की जान जा चुकी होती है। मोनिंदर का आरोप है कि जब वह मौके पर पहुंचे तब तक प्रशासन के लोग वहां मौजूद थे। युवराज कार की छत पर लेटा हुआ था और मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद की गुहार लगा रहा था। मोनिंदर बताते हैं, 'फायर ब्रिगेड की टीम के पास सीढ़ी थी, सेफ्टी जैकेट थी लेकिन वे किनारे बैठकर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पानी में उतरने को कहा और मैं कूद गया लेकिन वे पहले से वहां थे, उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की?' हैरानी की बात यह है कि इसी गड्ढे में करीब दो हफ्ते पहले भी एक ट्रक गिर गया था। उस समय भी मोनिंदर ने ही ट्रक ड्राइवर गुरिंदर की जान बचाई थी। गुरिंदर बताते हैं, 'इलाके में कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। मेरा ट्रक गड्ढे में गिरा तो मुझे लगा नीचे जमीन है लेकिन मैं सीधे पानी में जा गिरा। मोनिंदर ने रस्सी के सहारे मुझे बाहर निकाला, जब हमने नोएडा अथॉरिटी से मदद मांगी तो उन्होंने उल्टा मुझ पर ही दीवार तोड़ने का आरोप लगा दिया।' इससे ज्यादा अफसोसनाक और क्या हो सकता है कि पानी से भरे गड्ढे में अपनी कार के साथ फंसा एक युवक करीब डेढ़ घंटे तक मोबाइल की रोशनी के साथ जान बचा लेने की गुहार लगाता रहा और मौके पर मौजूद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल तथा दमकल विभाग का दल वहीं खड़ा अपनी लाचारगी का रोना रोता रहा। बचाव दल के पास तैराक और पर्याप्त वैकल्पिक संसाधन नहीं थे। जाहिर है, युवक की मौत की मुख्य वजह हादसे के बजाय संबंधित महकमों की घोर लापरवाही, बचाव दल की अक्षमता और अपर्याप्त संसाधन थी। यह कल्पना भी तकलीफदेह है कि किसी आपदा या आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के साथ ज्यादा से ज्यादा इंसानी जान को बचाने के लिए गठित दलों की मौजूदगी के बावजूद एक युवक की जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना में यह साफ देखने को मिला है कि हर संस्था ने अपने-अपने तर्क या यूं कहें कि बहाने गिना दिए। पुलिस ने कह दिया कि उसके लोगों को तैरना नहीं आता, फायर ब्रिगेड ने कह दिया कि उसके पास नाव नहीं थी और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तो आने में ही देरी लग गई। ऐसे में सवाल उठते हैं कि अगर करोड़ों खर्च करके कोई शख्स इन शहरों में रहने आया है तो क्या वह इन बहानों के सहारे ही जिएगा? क्या ऐसे हादसे होने पर नोएडा के लोगों को न्याय के नाम पर सिर्फ बहाने मिलेंगे?

गौतमबुद्ध नगर को प्रदेश के साथ-साथ देश का हाईटेक जिला माना जाता है। जिला प्रशासन की ओर से हर साल डीडीएमए की योजना तैयार की जाती है। हर आपदा से निपटने की कार्ययोजना तैयार की जाती है लेकिन इंजीनियर बचाने में संसाधनों की कमी देखने को मिली है। एसआईटी की टीम को मौके पर काफी खामियां मिली लेकिन अफसर बचाव करते नजर आए। टीम ने पूछा कि भूखंड में पानी कहां से आया तो प्राधिकरण के अफसरों ने बारिश का पानी बता दिया लेकिन टीम को जवाब सही नहीं लगा और कहा कि बारिश का पानी तो कब का सूख गया होगा। यह घटना नोएडा अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही को उजागर करती है। यह सड़क 10-12 साल से ऐसी ही है। सेक्टर-150 की सारी सोसाइटियों का वेस्ट वॉटर यहीं इकट्ठा होता है लेकिन अथॉरिटी ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब घटना के बाद बैरिकेट और पत्थर लगाए जा रहे हैं लेकिन पहले क्यों नहीं? स्थानीय निवासियों में भारी रोष है कि आखिर विकास के नाम पर खोदे गए इन 'मौत के कुओं' का जिम्मेदार कौन है? लोगों का कहना है कि घटना के अगले दिन भी किसी उच्च अधिकारी ने मौके पर पहुंचना जरूरी नहीं समझा लेकिन जब मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया तो

पुनरीक्षण की व्यवस्था

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकान्त व न्यायमूर्ति जायमाल्या ने यह कहकर कि मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कराने का चुनाव आयोग का अधिकार अक्षुण्ण तो है मगर असीमित नहीं है, स्पष्ट कर दिया है कि संविधान में गहन पुनरीक्षण की व्यवस्था है मगर यह पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इस प्रकार होनी चाहिए कि किसी भी वैध भारतीय नागरिक मतदाता के साथ पूर्ण न्याय हो सके। यह न्याय न केवल किया जाये बल्कि होता हुआ भी दिखे जिससे भारत का एक भी नागरिक स्वयं को पूरी तरह सन्तुष्ट महसूस करे। देश की सबसे बड़ी अदालत में उस याचिका पर सुनवाई हो रही है जिसमें गहन पुनरीक्षण की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। इस सन्दर्भ में स्वाभाविक प्रश्न यह है कि जब मतदाता सूची बनाने का विशिष्ट अधिकार चुनाव आयोग के पास है तो उसके शुद्धिकरण की जिम्मेदारी भी उसकी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए चुनाव आयोग को वह पूरी कवायद करनी होगी जिससे मतदाता सूचियों से अवैध मतदाताओं के नाम निकल सकें। इस कवायद को करने के लिए चुनाव आयोग को मतदाताओं की पहचान करनी पड़ेगी और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सूची में कोई भी ऐसा मतदाता न हो जिसका देहान्त हो गया हो और कोई भी व्यक्ति एक स्थान से अधिक स्थानों पर पंजीकृत न हो। इसके साथ-साथ हो प्रत्येक मतदाता का भारतीय नागरिक होना भी जरूरी है। जहां तक गहन पुनरीक्षण की संवैधानिकता का सवाल है तो सामान्य मोटी बुद्धि कहती है कि कोई भी वह कार्य किस प्रकार असंवैधानिक हो सकता है जिसका अधिकार संविधान ही चुनाव आयोग को देता है। हालांकि इस बारे में संसद के पिछले सत्र में खुलकर बहस हो चुकी है मगर इस बहस के बावजूद यह सत्य निकल कर बाहर नहीं आ सका कि गहन पुनरीक्षण कानून के किस नजरिये से असंवैधानिक कहलाया जा सकता है। इसी बारे में सर्वोच्च न्यायालय में अब तर्क-वितर्क देश के माने हुए कानूनविद कर रहे हैं जिसके बाद ही न्यायालय अपना अन्तिम फैसला देगा। बेशक यह कानून की पेचीदगियों का मामला है मगर इतना साफ है कि कानून सभी के साथ प्राकृतिक न्याय के पक्ष में होता है अतः पुनरीक्षण में हर उस नागरिक के साथ न्याय होना चाहिए जो पहले से मतदाता था मगर पुनरीक्षण के दौरान उसने अपना निवास बदल लिया है अथवा वह पलायन करके किसी अन्य स्थान पर जा बसा है। इस मामले में अभी तक देश के जिन 13 राज्यों (बिहार समेत) में पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है या पूरी हुई है उसमें चुनाव आयोग ने छह करोड़ के लगभग मतदाताओं के नाम सूचियों से काटे हैं जिससे साफ होता है कि मतदाता सूचियों में भारी अशुद्धियां थीं। मगर इसके साथ-साथ यह भी सच है कि बहुत से ऐसे जायज लोगों के नाम भी सूचियों से कट गये हैं जो चुनाव आयोग द्वारा मांगे गये प्रामाणिक प्रपत्रों की शर्तों को किसी वजह से पूरा नहीं कर सके। अतः ऐसे लोगों को भारत का संविधान मताधिकार से वंचित नहीं करता है क्योंकि संविधान में प्रत्येक नागरिक को मिला मत देने का ऐसा सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक अधिकार है जिस पर भारत का पूरा लोकतन्त्र टिका हुआ है। यह अधिकार ही भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का हक देकर तय करता है कि उसके मत से ही इस देश की सरकारों का गठन होगा और वे ही देश का शासन चलायेंगी। मतदाता की इस लोकतान्त्रिक भागीदारी को सहभागिता का लोकतन्त्र कहा गया क्योंकि इसमें मतदाता की सत्ता में सीधे भागीदारी होती है और वह ही इस देश का भाग्यविधाता कहा जाता है। यदि ऐसा न होता तो हर पांच साल बाद इस देश के प्रधानमन्त्री से लेकर साधारण विधायक तक को जनता की अदालत में वोट मांगने न जाना पड़ता और अपने किये गये कार्यों का हिसाब-किताब न देना पड़ता। वास्तव में वोट का हक ही भारतीय नागरिक को इस मुल्क का राजा बनाता है और उसे ही लोकतन्त्र का असली मालिक बनाता है। मतदाता का यह अधिकार सार्वभौमिक होता है जिसकी व्यवस्था संविधान में ही की गई है। इसके साथ ही मतदाता को भारतीय लोकतन्त्र स्वयंभू भी बनाता है क्योंकि चुनावों के समय उस पर कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता है। उसका मत गुप्त रहता है जिससे उसकी राजनैतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन होता है और फिर उसी के अनुसार देश में राजनैतिक सरकारों का गठन होता है मगर ये सरकारें केवल संविधान के अनुसार ही काम करती हैं, चाहे वे किसी भी राजनैतिक दल की हों। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में संविधान का शासन चलता है। इस सन्दर्भ में हम मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के कार्य की संवैधानिकता को परख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह प्रश्न भारत के लोकतन्त्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस वजह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों का यह कहना कि पुनरीक्षण का कार्य पारदर्शी तरीके से और प्राकृतिक न्याय को सर्वोपरि रखते हुए होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह विचार करना होगा कि आजादी के 78 वर्षों के बाद हमने जहां दिशा में जितनी भी तरक्की की है वह इसी व्यवस्था के तहत की है जिसमें भारत के मतदाताओं का विशिष्ट योगदान है क्योंकि समय की मांग के अनुसार इन्होंने अपनी राजनैतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करके विभिन्न दलों की सरकारों का गठन किया जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। जहां तक गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण का सवाल है तो स्वतन्त्र भारत के दौरान यह प्रक्रिया बार-बार हो चुकी है जिसकी मान्यता वह कानून जनप्रतिनिधित्व अधिनियम ही देता है जिसके तहत चुनाव आयोग का गठन हुआ है। अब सवाल इतना सा है कि जो भी पुनरीक्षण हो उसमें से किसी भी जायज भारतीय मतदाता का नाम न काटा जाये। इसे ही हम प्राकृतिक न्याय भी कहेंगे अतः चुनाव आयोग को ऐसी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो पूरी तरह पारदर्शी हो और भारत के हर मतदाता को सन्तोष प्रदान करने वाली हो।

सम्पादकीय...

शिक्षित पेशेवर आतंकवादी नैटवर्क

आतंकवाद को अक्सर गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक बहिष्कार का परिणाम माना जाता है। लेकिन भारत सहित दुनिया भर के अनुभव बताते हैं कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। हाल के वर्षों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें उच्च शिक्षित और पेशेवर रूप से प्रशिक्षित लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए गए। अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े चिकित्सकों का मामला इसी असहज वास्तविकता की ओर संकेत करता है। प्रश्न उठता है कि शिक्षा, जो विवेक और समझ विकसित करने का माध्यम मानी जाती है, कभी-कभी चरमपंथ को रोकने में क्यों विफल हो जाती है? शिक्षा अपेक्षाएं बढ़ाती है। जब ये अपेक्षाएं सीमित अवसरों, संस्थागत अव्यवस्था या व्यक्तिगत असफलताओं से टकराती हैं, तो निराशा तीव्र हो जाती है। पुलिसिंग के अनुभव से यह स्पष्ट है कि सापेक्ष वंचना, यानी जो मिलना चाहिए था और जो मिला, उसके बीच का अंतर, अक्सर पूर्ण गरीबी से अधिक प्रभावी होता है। शिक्षित व्यक्ति असफलता को भाग्य नहीं, अन्याय के रूप में देखने लगता है। विश्वविद्यालय और पेशेवर संस्थान कौशल तो सिखाते हैं, लेकिन सोहबत और उद्देश्य प्रदान करने में अक्सर पीछे रह जाते हैं। घर से दूर, परिचित सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचे से बाहर काम कर रहे युवा पेशेवर अकेलेपन का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे समय में संगठित वैचारिक समूह-धार्मिक हों या राजनीतिक-सदस्यता, पहचान और उद्देश्य देते हैं। वे व्यक्तिगत असमंजस को सामूहिक मिशन में बदल देते हैं। एक कम चर्चित पहलू यह भी है कि शिक्षा तर्कशक्ति को तेज करती है लेकिन नैतिक संयम अपने-आप नहीं देती। उच्च शिक्षा में सिखाए गए औजार- तर्क, अमूर्तन और प्रणालीगत सोच, हिंसा को चुनौती देने के लिए भी उपयोगी हैं और उसे सही ठहराने के लिए भी। चरमपंथी विचारधाराएं सुव्यवस्थित कथानकों पर आधारित होती हैं, जिनमें हिंसा को आवश्यक, रक्षात्मक या नैतिक रूप से श्रेष्ठ बताया जाता है। शिक्षित व्यक्ति ऐसे तर्कों को अधिक कुशलता से आत्मसात कर सकता है। यह अज्ञान नहीं, बल्कि बुद्धि का दुरुपयोग है। संगठनात्मक दृष्टि से शिक्षित पेशेवर आतंकवादी नैटवर्क के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे नैटवर्क भी किसी जटिल संगठन की तरह काम करते हैं-उन्हें वित्त, लॉजिस्टिक्स, तकनीकी दक्षता और विश्वसनीयता चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक ये सब प्रदान करते हैं। उनकी मौजूदगी नैटवर्क को क्षमता देती है और गंभीरता का संकेत भी। यही कारण है कि विभिन्न क्षेत्रों में चरमपंथी संगठन पेशेवरों की सक्रिय भर्ती करते रहे हैं। संस्थागत कमजोरियां इस खतरे को बढ़ाती हैं। विश्वविद्यालय और पेशेवर निकाय सुरक्षा एजेंसियां नहीं हैं और उन्हें होना भी नहीं चाहिए लेकिन कमजोर प्रशासन, अपर्याप्त पृष्ठभूमि जांच और सीमित मार्गदर्शन ऐसे ब्लाइंडस्पॉट सृजित करते हैं, जिनका दुरुपयोग संभव है। जब संस्थान केवल डिग्री और परिणाम पर केंद्रित रहते हैं और नैतिकता, नागरिक जिम्मेदारी तथा छात्र-कल्याण को गौण मानते हैं, तो प्रारंभिक चेतावनी संकेत अनदेखे रह जाते हैं।

शोधों के अनुसार शादीशुदा लोगों में तनाव व अवसाद का स्तर

शादी का बंधन केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि एक संवेगात्मक सम्बल का साधन है। कुछ लोग जीवन भर अविवाहित रहकर किसी विशेष कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं। अविवाहित लोग अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं, जो मानसिक समस्याएं पैदा करने लगता है। शादीशुदा जीवन में परिवार व बच्चों का साथ भी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। अविवाहित लोगों में अकेलापन, सामाजिक दबाव व रिश्ते बनाने में कठिनाई जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं।

शोधों के अनुसार शादीशुदा लोगों में तनाव व अवसाद का स्तर अविवाहित लोगों की अपेक्षा कम होता है। अविवाहित लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम अधिक होता है। जीवन में अकेली महिलाओं पर शोध दर्शाते हैं कि महिलाएं स्वास्थ्य समस्याओं, गंभीर चोट, दुर्घटना तथा समायोजन संबंधी कठिनाइयों से जूझती हैं। उन्हें आर्थिक रूप से प्रतिकूल स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। अधिकांश अविवाहित महिलाएं यौन उत्पीड़न के भय से ग्रस्त रहती हैं जिससे उन्हें कई मनोवैज्ञानिक बीमारी, निराशा, दुश्चिंता, उदासी, अवसाद विकार व अलगाव की भावना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार विवाहित लोगों की तुलना में सिंगल लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा 5प्रतिशत ज्यादा होता है। विश्व में लगभग 47.35 मिलियन पुरुष तथा महिलाओं लगभग 41.81 मिलियन अविवाहित हैं। पिछले दो दशकों में अविवाहित व्यक्तियों की संख्या लगभग 21 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 35 प्रतिशत हो गई है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 23 प्रतिशत युवा शादी नहीं करना चाहते हैं। 2019 में पुरुषों की लगभग 26.1प्रतिशत तथा महिलाओं की लगभग 19.9प्रतिशत आबादी शादी नहीं करना चाहती थी। एक तरह से देश के एक चौथाई से ज्यादा युवा लड़के-लड़कियां शादी नहीं करना चाहते। सरकार की एक रिपोर्ट (2019) के अनुसार शादी न करने वाले युवाओं की सबसे अधिक संख्या जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दर्ज की गई है। अविवाहित व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति अलग पाया गया है जहाँ कुछ को अकेलापन व अवसाद का खतरा होता है, वहीं कुछ मजबूत सामाजिक नेटवर्क, स्वतंत्रता व व्यक्तिगत विकास से बेहतर महसूस करते हैं। एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह लेख गृहस्थ जीवन में रहने वालों को ध्यान में रखकर लिखित है। बैराग्य धारण करने वाले साधु संतों के लिए अविवाहित जीवन परम आनंद दायक व उत्तम मानसिक स्वास्थ्य का साधन होता है क्योंकि उनकी जीवनशैली, दिनचर्या, सोच विचार, अपेक्षाएँ, इच्छाएँ सामान्य व्यक्ति से अलग होता है।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं-

अकेलापन- जीवनभर अकेले रहने से अकेलापन महसूस होता है, खासकर जब आसपास के लोग शादीशुदा हों। परिवार का एकांकी होना। अस्वस्थ होने पर देखभाल हेतु लोगों के उपलब्ध न होने पर अविवाहित की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।

सामाजिक दबाव- समाज द्वारा अविवाहित होने पर दबाव देना आम बात है क्योंकि अविवाहित रहना सामाजिक मानक के खिलाफ है जिससे सामाजिक दबाव होता है कि शादी कर लें। जिससे व्यक्ति खुद को अलग-थलग समझने लगता है।

रिश्तों की चिंता- एक समय के बाद खास कर माता पिता के मृत्यु हो जाने पर कोई साथी न मिलने या गलत साथी मिलने की चिंता सताने लगती है। उम्र ढलने के साथ मित्र व रिश्तेदारों से भी सम्पर्क कम होने लगता है जिससे चिंता और बढ़ जाती है।

आत्म-सम्मान में कमी- अकेलापन व सामाजिक दबाव के कारण अविवाहित लोगों के आत्म-सम्मान में कमी आने लगता है जिससे नकारात्मकता बढ़ने लगती है।

अवसाद - लगातार अकेलापन व निराशा की भावना से अवसाद होता है। व्यक्ति अपने रुचिकर कार्यों में भी अरुचि रखने लगता है उसका जीवन में उम्मीद कम तथा निराशा बढ़ता है। समय रहते इसका प्रबंध न किया जाए तो व्यक्ति में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं तथा आत्महत्या का प्रयास भी व्यक्ति कर सकता है।

बचाव-

सामाजिक नेटवर्क बनाएं- दोस्तों, परिवार और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाएं। लोगों का सहयोग करें ताकि लोग आप को भी सहायता करें।

शौक को पूरा करें- अपने अच्छे शौक की पहचान कर उसे पूरा करें तथा कोई गलत शौक हो तो उसे दूर करने का प्रयास करें। शौक के माध्यम से कौशल विकास करने का प्रयास करें।

व्यक्तिगत विकास- यात्रा करें, डायरी लिखें, संगीत सुने। ऐसे काम करें जो आपको खुशी दें और व्यक्तिगत विकास में मदद करें। अच्छे गुणों की पहचान कर उसे और विकसित करें।

स्वयं- देखभाल- स्वस्थ आहार, पर्याप्त पानी पीएं, व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। कैफीन और शराब का सेवन सीमित करें। नियमित दिनचर्या अपनाएँ, हो सके तो सहायक रखें।

सकारात्मक दृष्टिकोण रखने- विवाहित होने के बजाय अविवाहित होने के फायदों पर ध्यान दें। सकारात्मक सोचें, भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं बनाएँ। आवश्यकता होने पर सहयोग लेने में संकोच न करें।

दुविधा में न रहें ले स्पष्ट निर्णय- ऐसा पाया गया है कि जो लोग अविवाहित रहने की कमजोर इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं उनमें असमंजस और अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है जिससे उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ती है इसलिए यदि एक बार अविवाहित रहने का निर्णय लो उस पर दृढ़ रहो।

पेशेवर मदद लें- यदि अकेलापन या अवसाद हो तो मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से बात करें। वे भावनाओं को समझने और नकारात्मकता से निपटने में मदद करते हैं। विभिन्न एक्सरसाइज से तनाव कम करने में सहयोग दे सकते हैं।

समूह से जुड़ें- अविवाहित लोगों व समान अनुभवों वाले लोगों के समूहों में शामिल होना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में सहायक होता है। अपनी भावनाओं को साझा करने व समझने में आसानी होती है।

शादी का लें निर्णय- अविवाहित यदि अकेले रहने से लंबे समय तक व गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहें हो तो उन्हें एक बार शादी कर लेने का गंभीरता से विचार करके निर्णय लेना चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अविवाहित लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है इसके लिए अपने सामाजिक नेटवर्क को मजबूत करना, दोस्तों और परिवार से जुड़ाव, शौक को पूरा करना महत्वपूर्ण है। अकेलेपन को दूर करने के लिए व्यक्ति को अपनी रुचियों व सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहना अच्छा होता है। नियमित योग, ध्यान और व्यायाम करने से भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अपने आप हमेशा अच्छे व रुचिकर कार्यों व्यस्त रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम है।

भारतीय दिलों की पारंपरिक लोकतांत्रिक सोच

स्वाधीनता के बाद जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने अपनाया, वह हमारी अपनी नहीं, पश्चिम से आयातित है। दिलचस्प है कि आज यही व्यवस्था दुनियाभर में शासन की बेहतर प्रणाली के रूप में स्वीकार्य है। इसकी बुनियाद में इंग्लैंड की सन् 1215 में हुई मैग्नाकार्टा की संधि है। आज का लोकतंत्र इसी संधि से निकले कानूनों और परंपराओं से विकसित हुआ है। जबकि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल में भारतीय दिलों की पारंपरिक लोकतांत्रिक सोच है। दुर्भाग्य से भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की महत्ता को दुनिया हाल तक स्वीकार करने से हिचकती रही है। ऐसे माहौल में अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक एवं चुनावी सहायता संस्थान की अगुआई भारत को मिलना मामूली बात नहीं है। अंग्रेजी में इस संस्थान को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी आईडीईए के नाम से जाना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारतीय लोकतंत्र की अहमियत वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य हो रही है। वैश्विक लोकतांत्रिक परिदृश्य के लिहाज से भारत को मिली अगुआई ऐतिहासिक है। 1995 में 14 देशों द्वारा स्थापित इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या अब 37 हो चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान स्थायी पर्यवेक्षक के तौर पर इस संगठन में शामिल हो चुके हैं। करीब आठ अरब जनसंख्या वाली दुनिया के करीब दो अरब बीस करोड़ पंजीकृत मतदाता इसी संगठन के सदस्य देशों के पास हैं। जिसमें भारत की हिस्सेदारी 99 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। आंकड़ों से साफ है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। इस लिहाज से देखें तो भारत की अध्यक्षता उसके लिए औपचारिक दायित्व से कहीं ज्यादा वैचारिक नेतृत्व का अवसर हो सकती है। इस संगठन में सदस्य देशों के चुनाव आयोग या चुनाव कराने वाली संस्थाएं ही शामिल होती हैं, लिहाजा भारतीय चुनाव आयोग इस संस्था का सदस्य है। जाहिर है कि इसी नाते अध्यक्षता भी आयोग के ही पास है। जिस वक्त घरेलू मोर्चे पर भारतीय चुनाव प्रणाली और मशीनरी सवालों के घेरे में है, उसी वक्त भारतीय चुनाव आयोग को इस प्रतिष्ठित संस्था की अगुआई मिली है। घरेलू मोर्चे पर विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग पर कभी वोट चोरी का आरोप लगाया जाता है तो कभी नकारा बताया जाता है। ऐसे वातावरण में चुनाव आयोग को आईडीईए की अध्यक्षता मिलना सामान्य बात नहीं, बल्कि भारतीय चुनाव प्रणाली की वैश्विक स्वीकृति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। दुनिया अब तक लोकतंत्र को -पश्चिमी मॉडल- के चश्मे से ही देखती रही है। जबकि इसके मूल में लोकतांत्रिक आत्मा नहीं, बाजार केंद्रित राजनीतिक ढांचा है, जहां व्यक्ति की बजाय संस्थाओं की स्वाधीनता और संसदीय परंपराओं पर जोर है। संचार और सूचना क्रांति एवं आर्थिक बदलावों के चलते आज का मतदाता बेहद जागरूक हो चला है। वह अपनी निजी राय की अहमियत को भी चाहत रखता है। इस वजह से पश्चिमी मॉडल वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सोच बदली है। भारतीय लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था अगर तनकर खड़ी है, तो उसके पीछे इन वैचारिक बदलावों का बड़ा योगदान है। एक अरब की भारी-भरकम मतदाता संख्या वालेभारतीय चुनावी तंत्र में भागीदारी बढ़ना मामूली बात नहीं है। इसे भारतीय चुनावी तंत्र की लचीली किंतु मजबूत व्यवस्था की सफलता के रूप में भी देखा जाना चाहिए। भारतीय चुनावी प्रबंधन में बढ़ते नवाचार, डिजिटल चुनावी प्रबंधन पर जोर, दिव्यांग और दुरस्थ मतदाताओं तक बढ़ती पहुंच, के लिए चुनाव आयोग की सोच ज्यादा जिम्मेदार है। चुनावी साक्षरता बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग ने जितने प्रयोग किए हैं, वैसा उदाहरण कहीं और नहीं दिखता। विपक्षी सवालों के बावजूद चुनावों में अगर मतदाता भागीदारी बढ़ी है, तो माना जा सकता है कि चुनाव आयोग के प्रति भरोसा कम नहीं हुआ है। इस लिहाज से देखें तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहुंच पुस्तकालयों और विमर्श के संस्थागत मंचों की बजाय बूथ और अंतिम व्यक्ति तक बढ़ी है। इस संदर्भ में चुनाव आयोग की अध्यक्षता में 21 से 23 जनवरी के बीच आईडीईए देशों के चुनाव प्रमुखों और अधिकारियों की होने जा रही बैठक बेहद अहम हो जाती है। माना जा रहा है कि आयोग से दुनियाभर के अधिकारी जानना चाहेंगे कि मतदाताओं की भारी संख्या के बावजूद आयोग उन तक कैसे पहुंचता है और चुनाव प्रणाली की पवित्रता कैसे बरकरार है। चुनावी पवित्रता की नाभि-नाल पारंपरिक लोकतांत्रिक प्रणाली से जुड़ी है। प्राचीन भारत का वज्जि गणतंत्र आधुनिक प्रणाली से कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक और लोकोन्मुखी था। दक्षिण भारत के दसवीं सदी के चोल शासकों ने ग्रामीण शासन व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था अपना रखी थी, उसे आधुनिक राजनीति विज्ञानी भी बेहतरीन प्रणाली मान रहे हैं। मैग्नाकार्टा के कुछ साल पहले कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत बसवेश्वर ने जिस अनुभव मंडपम् की स्थापना की थी, उसमें समाज के हर वर्ग के लोग धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते थे और एक परिणति तक पहुंचते थे। राजनीति शास्त्री इसे आधुनिक संसद का प्रथम स्वरूप मानते हैं। आज हमारी चुनाव प्रणाली मजबूत है तो इसकी एक वजह हमारी यह परंपरा भी है। वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक राष्ट्रों के समक्ष चुनौतियां बढ़ी हैं। जिनके लिए भारत का अनुभव प्रेरक हो सकता है। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के लिए ध्रुवीकरण, दुष्प्रचार और बाहरी हस्तक्षेप, चुनावी धन में पारदर्शिता की कमी एवं युवाओं की घटती रुचि खतरा बन रही है। इसमें जनमत को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल ने कोढ़ में खाज का काम कर रहा है। ऐसे माहौल में भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर चुनावी लिहाज से अपने सफल मॉडल आधारित अनुभव से लोकतांत्रिक राष्ट्रों की चुनाव प्रणाली के लिए प्रेरक हो सकता है। भारत को इन देशों की अगुआई इस बात का भी प्रतीक है कि हमारे लोकतंत्र की ताकत सिर्फ चुनाव में नहीं, बल्कि हर वोट को मिली अहमियत से है। इसी वजह से विविधरंगी समाज, भाषा, धर्म और असमानता के बावजूद भारतीय चुनाव प्रणाली शांतिपूर्ण बनी हुई है। साफ है कि विशाल और बहुलवादी समाज भारतीय लोकतंत्र की बाधा नहीं, ताकत है। पश्चिमी और ग्लोबल साउथ देशों की लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों के मद्देनजर भारतीय चुनाव प्रबंधन कहीं ज्यादा उपलब्धि भरा है। अमेरिका और यूरोप में जहां मतदाता भागीदारी लगातार कम हो रही है, वहीं अविश्वास और आपसी सामाजिक टकराव जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इसके बरक्स विविधता के बावजूद हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था समस्या समाधान का शांतिपूर्ण हथियार बनी हुई है। इसमें महिलाओं, दिव्यांगजनों और युवा मतदाताओं के साथ बढ़ी मतदाता भागीदारी ने लोकतांत्रिक जड़ों को गहरा ही किया है। आमजन की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जारी विश्वास भी इसी का प्रतीक है। आज मौका मिलते ही सरकारें बदलने और दूसरी पार्टी को मौका मिलती है तो इसकी वजह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर बढ़ती जागरूकता और उसके प्रति अटूट भरोसा है। विविधरंगी, अलग सामाजिक पहचान, जाति, धर्म और भाषा, क्षेत्रीय भिन्नताएं अलग होने के बावजूद अगर भारत में पश्चिम की तरह टकराव नहीं है तो उसकी वजह लोकतांत्रिक और चुनाव प्रक्रिया में अटूट भरोसा ही है। साफ है कि विविध सामाजिक पहचान के साथ सामुदायिक संतुलन और सहअस्तित्व भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता की गारंटी बना हुआ है। इसके पीछे चुनाव आयोग की सोच भी है। आज चुनावी नवाचार में भारत अगुआ है। ईवीएम, वीवीपैट, महिलाओं एवं दिव्यांग संचालित एवं थीम आधारित मतदान केंद्र, पोस्टल बैलेट, सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित मतदाता सेवाएं और स्वीप जैसी जागरूकता पहल तेजी और व्यापक तरीके से लागू की जा रही हैं। इनके चलते भारत में लोकतंत्र का भविष्य पश्चिमी देशों की तुलना में अधिक विस्तारित, स्थायीत्व और जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से वैश्विक विमर्श में -भारतीय चुनाव मॉडल- प्रेरक बन चुका है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/08862)

सांस्कृतिक प्रदूषणः समस्या और समाधान पर खुले मंच पर हुई परिचर्चा

मुरादाबाद।

उदीषा साहित्योत्सव

उदीषा उत्सव- 2026 का आयोजन स्थानीय गाँधी मैदान, बुद्धि विहार में 22 से 26 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका आयोजन आयुक्त मुरादाबाद मण्डल आन्जनेय कुमार सिंह के निर्देशन में हो रहा है जिसके अंतर्गत भारतीय ललित कलाओंके क्षेत्र के बड़े- बड़े कलाकार भाग ले रहे हैं! कार्यक्रम के दूसरे दिन सांस्कृतिक प्रदूषणः समस्या और समाधान विषय पर खुले मंच पर चर्चा हुई! इस चर्चा का आयोजन हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और उ. प्र. द्वारा साहित्यभूषण सम्मान से विभूषित हिंदी के आचार्य डा. महेश दिवाकर ने किया। इसमें दैनिक बिजनौर टाइम्स एवं चिंगारी, बिजनौर के संपादक डा. सूर्यमणि रघुवंशी, श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता, मुरादाबाद, प्रो. कैप्टन डा. राजीव चौहान और डा. मीनाक्षी ठाकुर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे! कार्यक्रम के आरंभ में जिला प्रशासन मुरादाबाद की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट श्री विनय पान्डे ने चारोंअतिथि वक्ताओं का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कार्य क्रम के आरंभ में संचालक एवं प्रवर्तक डा. महेश दिवाकर ने अपना बीज वक्तव्य देकर सांस्कृतिक प्रदूषण का परिचय देते हुए इस विषय की महत्ता पर प्रकाश डाला! तत्पश्चात प्रो. डा.

कैप्टन राजीव कुमार ने अपने वक्तव्य में संस्कृति को परिभासित करते हुए विविध प्रकार के सांस्कृतिक प्रदूषण पर प्रकाश डालते हुए शैक्षिक और वाणीगत प्रदूषण को रोकने के लिए शैक्षिक जागरूकता पर बल दिया। अपने वक्त पर कैप्टन डॉ. राजीव चौहान ने कहा कि श्रेष्ठ साहित्य से ही राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव है। युवाओं को साहित्य से जुड़ना होगा ताकि तथ्यात्मक जानकारी हासिल कर सके। ऐडवोकेट सुधीर गुप्ता ने कहा कि समाज की परंपराएं, मूल्य, भाषा, कला रीति-रिवाज और पहचान नकारात्मक प्रभावों के कारण कमजोर या लुप्त होने लगी है। इस अवसर पर लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार एवं संपादक डा सूर्य मनी रघुवंशी ने कहा कि हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति का आधार धर्म है, पुराणों का ज्ञान है और भागवत गीता का उपदेश है। उन्होंने राजनीतिक विद्रूपता के कारण सनातन के प्रदूषण की चर्चा की और इसके सुधार के लिए अनेक उपायों की चर्चा की उन्होंने बढ़ते बाजारवाद और गहराते प्रदूषण की चर्चा भी की! उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रदूषण की चर्चा की! और स्वस्थ पत्र कारिता करने के लिए प्रेरित किया! इसी क्रम में श्रीमती मीनाक्षी ठाकुर ने कहा कि आज की फिल्म शिक्षाप्रद न होकर फूहड़ मनोरंजन का साधन बन गई है। युवा पीढ़ी पर जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अंत में शिक्षा, जागरूकता पत्रकारिता और साहित्य की महत्ता की ओर डा. महेश दिवाकर ने इंगित करते हुए प्रदूषण के उन्मूलन की ओर संकेत किया! अंत में उपस्थित सभी अतिथियों को सॉल पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम का संचालन एवं विषय प्रवर्तन का सफलता पूर्वक संयोजन वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर डा महेश दिवाकर ने किया।

सुभाष चंद्र बोस के बलिदान से हुई देश और धर्म की रक्षा

मुरादाबाद।

आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद पर धर्म रक्षक बाल हकीकत का 291वां बलिदान दिवस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129 वीं जयंती मनायी गयी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के महामंत्री धवल दीक्षित रहे मुख्य वक्ता आर्य मनीषि कपिलमुनि रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में शिवम् आर्य ने देशभक्ति और धर्म व संस्कृति और बलिदान से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत किये। इस अवसर पर आर्य मनीषि कपिलमुनि ने बताया कि धर्म का मूल वेद है व लेकिन धर्म की रक्षा त्याग और बलिदान से होती है। 17वी शताब्दी में भारत में मुगल शासक शासन कर रहे थे। ऐसे में 16वर्षीय बाल हकीकत का मात्र झूठे आरोपों पर गर्दन काटकर बसंत पंचमी को बलिदान कर दिया। हम उनके धर्म रक्षक बलिदान से प्रेरणा लेकर धर्म के प्रति आशक्तिवान रहे। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश की आजादी में प्रमुख योगदान का भी उल्लेख किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस आव्हान ने युवाओं में विशेष प्रेरणा मिली और आजादी की क्रांति से जुड़ गये। आयोजन में मंत्री रमेश सिंह आर्य एडवोकेट, करनसिंह आर्य, सुदेश आर्य,अदिति खुशबू अमित आर्य मीरा देवी यशोदा रामाशंकर आर्य,प्रभा आर्य और मयंक आर्य आदि उपस्थित रहे। वहीं, जिला बार एसोसिएशन मुरादाबाद में आज सुभाष चन्द्र बोस जयंती पर एक विचार गौष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने श्री बोस के जीवन चक्र पर प्रकाश डाला। ब्रिट्रीश सरकार से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनका एक नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा,ने जनजन में जोश ला दिया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शिरीष महरोत्रा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अजयगुप्ता डीजीसी सिविल मुरादाबाद, ललित अरोड़ा, अनिल पाल सिंह, जयवीर सिंह, ध्रुव कुमार सक्सेना, हर स्वरूप, भीकम सिंह सैनी,शेर सिंह बौद्ध, संध्या दीक्षित, गोपाल कृष्ण, एएच जैदी, सोमपाल सिंह, हर स्वरूप, वीरेंद्र चौहान, संजीव सक्सेना आदि ने प्रतिभाग किया। अंत में मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हर प्रसाद ने की संचालन महामंत्री सरदार प्रकाश वीर सिंह ने किया।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक पहल

प्रयागराज।

नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), जमुनीपुर, प्रयागराज के विशेष शिक्षा संकाय तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगजन का समग्र सशक्तिकरण चिकित्सीय, सामाजिक, शैक्षणिक एवं विधिक परिप्रेक्ष्य विषय पर द्विदिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन अत्यंत गरिमामय एवं प्रेरक वातावरण में संपन्न हो रहा है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगता के विविध प्रकारों, उनके कारणों, शीघ्र पहचान, निदान तथा चिकित्सीय पुनर्वास के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न करना है। साथ ही सहायक उपकरणों, कृत्रिम अंगों, आधुनिक पुनर्वास तकनीकों, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, मनोसामाजिक देखभाल, समावेशी शिक्षा तथा सहायक आईसीटी उपकरणों की भूमिका को रेखांकित करते हुए दिव्यांगजनों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप एवं प्रभावी पुनर्वास की आवश्यकता पर बल दिया गया। कार्यशाला के प्रथम दिवस की मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता कमलाकांत पाण्डेय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सक्षम तथा सदस्य एवं सलाहकार, दिव्यांगता सलाहकार परिषद,

भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की विधिक भाषा, उसके प्रभावी अनुपालन एवं अधिकार-आधारित दृष्टिकोण पर सारगर्भित वक्तव्य प्रस्तुत कर प्रतिभागियों को विधिक जागरूकता से सशक्त किया।

विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता डॉ. नीता मिश्रा, सहायक आचार्य, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज ने समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा दिव्यांग-अनुकूल शिक्षण व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा को सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बताया। विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा संकाय की सहायक आचार्य रश्मि मौर्य ने सामाजिक समावेशन एवं समुदाय आधारित पुनर्वास की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. दीपक त्रिपाठी, सहायक आचार्य, विशेष शिक्षा संकाय, नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय ने प्रारंभिक हस्तक्षेप, निदान एवं चिकित्सीय पुनर्वास के महत्व को विस्तार से रेखांकित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्यामसुंदर मिश्रा ने की।

टीएमयू संग आत्मीय रिश्तों को और प्रगाढ़ कर गए मशहूर गायक सुखविंदर सिंह

मुरादाबाद।

बसंत पंचमी से एक दिन पूर्व जाने-माने पंजाबी सिंगर सुखविंदर सिंह तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी परिवार के संग अपने प्रगाढ़ रिश्तों को और सुगंधित कर गए। उदीषा चौपाल साहित्योत्सव-2026 में शिरकत करने मुरादाबाद आए सुखविंदर अपनी चहेती तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी आना नहीं भूले। चल छैया-छैया..... और जय हो... सरीखे मशहूर गानों के पार्श्व गायक सुखविंदर का कुलाधिपति सुरेश जैन और जीवीसी मनीष जैन ने अपने आवास- संवृद्धि में मंगल आगमन पर बुके देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर फर्स्ट लेडी वीना जैन, ऋ चा जैन, एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अक्षत जैन, नंदिनी जैन आदि की उल्लेखनीय मौजूदगी रही। पर्यावरण प्रेमी सुखविंदर कुलाधिपति आवास-संवृद्धि में खिले गेंदों के फूल देखकर गदगद हो गए। सुखविंदर मानते हैं, टीएमयू इन्नोवेटिव विजन, डायनामिक लीडरशिप, पर्यावरण, स्टार्ट अप्स, क्रिएटिविटी, रिसर्च के प्रति बेहद सजीदा है। साथ ही जैन परिवार ऊर्जावान है। जिंदादिल है। अभिनंदन के योग्य है। उल्लेखनीय है, टीएमयू परिवार का पंजाबी सिंगर सुखविंदर से बरसों पुराना आत्मीय रिश्ता है। दीक्षांत समारोह के रॉक ऑन से लेकर कल्चरल नाइट्स में अपनी जादुई आवाज से महफिल लूट चुके हैं। उल्लेखनीय है, टीएमयू को अपना ही परिवार एवं कुलाधिपति सुरेश जैन को अज़ीम शख्सियत मानने वालेसुखविंदर का यूनिवर्सिटी के संग बरसों से दिली लगाव है। कोविड काल के दौरान 2020 में एक अविस्मरणीय वीडियो जारी करके टीएमयू से अपने अंतरंग रिश्तों को सार्वजनिक कर चुके हैं। टीएमयू हॉस्पिटल को तीर्थ की संज्ञा देते हैं। कह चुके हैं, टीएमयू हॉस्पिटल जैन परिवार के लिए धन कमाने की अपेक्षा जनसेवा का जरिया है। उल्लेखनीय है, हॉस्पिटल के सेवा, संकल्प और समर्पण के बूते यूपी सरकार कोविड काल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उम्दा इलाज के लिए ए श्रेणी का दर्जा दे चुकी है। मैं यूनिवर्सिटी के भव्य एवम् हरित कैंपस के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हूं। 2019 में अमर उजाला के कंसर्ट में आए तो उन्होंने कुलाधिपति परिवार को मंच पर बुला लिया। कुलाधिपति से गर्मजोशी में गले मिलते हुए बोले, अब मेरा तन-मन और मेरी आवाज खुशियों से लबरेज हो गई है। यह दिली रिश्ता परस्पर है। 2023 में संवृद्धि आए तो गोल्फ कार्ट से सुखविंदर समेत पूरे परिवार ने कैंपस का भ्रमण कराया, जबकि ड्राइविंग सीट की कमान खुद एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अक्षत जैन ने संभाली।

बूंदाबांदी के बीच स्वयंसेवकों ने रामगंगा तट पर की सफाई

मुरादाबाद।

कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती की पूजा अर्चना से हुआ एवं सभी ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए।

चित्रगुप्त इण्टर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के ग्राम मोरा मुस्तकम में आयोजित हो रहे विशेष शिविर के छठा दिवस रामगंगा सफाई एवं यातायात जागरूकता के नाम रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती की पूजा अर्चना से हुआ एवं सभी ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रथम सत्र में स्वयंसेवकों ने हल्की बूंदाबांदी के बीच रामगंगा नदी के तट पर पहुचकर तटो की सफाई की एवं नदी के तट पर कूड़ा कर्कट को उपयुक्त स्थान पर फेंका। साथ ही वहां फेंकी गयी पूजा सामग्री एवं मूर्तियों को वहां से उठाकर वहां गड्ढे खोदकर दबाया।स्वयंसेवकों द्वारा वहां से निकल रहे राहगीरों को नदी में कूड़ा-करकट न फेंकने का अनुरोध किया। द्वितीय सत्र को यातायात दिवस के रूप में मनाया गया। यातायात पुलिस विभाग से पधारे यातायात उप निरीक्षक प्रवीन कुमार ने स्वयंसेवकों को यातायात नियमों के पालन के महत्व को समझाते हुए बताया कि स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, जाम से बचने और व्यवस्थित ट्रैफिक प्रवाह बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह कानून का सम्मान करने, कीमती जान बचाने, कानूनी कार्रवाई (चालान) से बचने और यात्रा को सुगम बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।हेड कांस्टेबल कपिल राणा ने नियमों के उल्लंघन करने पर कटने वाले चालानों के सम्बन्ध में जानकारी दी एवं सुरक्षित वाहन चलाने एवं नियमों के पालन करने का संदेश दिया। अध्यक्षता कार्यक्रम अधिकारी डॉ राजीव कुमार ने की एवं संचालन डॉ विशेष कुमार शर्मा ने किया।इस अवसर पर शौर्य कुमार, यशराज सिंह,देव,फैज खान, अरमान,अंश,शिवा, रोहित कुमार, वासुदेव ने सहयोग किया।

शशि थरूर का बगावती तेवर! कोचि में हुए अपमान के बाद कांग्रेस की हाई-लेवल बैठक से बनाई दूरी

नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। पार्टी के दिग्गज नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने राज्य चुनाव की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस आलाकमान द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, थरूर का यह कदम हाल ही में कोचि में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुए अपमान के प्रति उनके कड़े विरोध को दर्शाता है। सूत्रों के अनुसार, यह फैसला तब लिया गया जब थरूर को कोचि में एक महापंचायत कार्यक्रम में अपमानित महसूस हुआ, जहां पार्टी सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे। अहम चर्चा मीटिंग से थरूर की गैरमौजूदगी हाई-स्टेक वाले राज्य चुनावों से पहले पार्टी के अंदरूनी मतभेद का संकेत देती है। कांग्रेस सूत्रों ने संकेत दिया है कि वह फिलहाल कांग्रेस के राज्य और केंद्रीय नेतृत्व दोनों से नाराज़ हैं, जिसके कारण उन्होंने मीटिंग में शामिल न होने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, थरूर ने अपने करीबी सहयोगियों को अपनी निराशा बताई है, और कहा है कि यह घटना पार्टी के अंदर उनके योगदान को अनदेखी के एक बड़े पैटर्न को दिखाती है। कोचि इवेंट में, बैठने और बोलने के शेड्यूल को लेकर दिक्कतें आईं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, थरूर को बताया गया था कि उनके बाद सिर्फ राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन बाद में दूसरे नेताओं ने भी भाषण दिया। व्यवस्थाओं को लेकर यह कन्फ्यूजन सार्वजनिक अपमान के तौर पर देखा गया, खासकर कांग्रेस में थरूर की वरिष्ठता को देखते हुए। शुरुआती निर्देश के बावजूद, राहुल गांधी के आने के बाद कई अन्य पार्टी नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, तय प्लान से यह बदलाव थरूर की नाराजगी का कारण बना, खासकर वक्ताओं के क्रम के संबंध में प्रोटोकॉल के उल्लंघन को देखते हुए।

इस घटना ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आंतरिक अनुशासन और वरिष्ठ नेताओं के सम्मान के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। महापंचायत में अपने भाषण के दौरान, राहुल गांधी ने थरूर का नाम नहीं लिया। पर्यवेक्षकों ने कहा कि थरूर की पार्टी और राज्य में प्रमुखता को देखते हुए यह बात ध्यान देने योग्य थी। सूत्रों ने बताया कि पहचान की कमी ने थरूर द्वारा व्यक्त की गई कुल मिलाकर असंतोष की भावना में योगदान दिया। हालांकि थरूर कांग्रेस हाई कमान की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वह आज केरल साहित्य महोत्सव में हिस्सा लेने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने थरूर की कथित परेशानी या केरल चुनाव मीटिंग में शामिल न होने के उनके फैसले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान या राहुल गांधी की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि, पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं।

दक्षिण की पथरीली जमीन पर कमल खिलाने उतरे मोदी

केरल।

दक्षिण की पथरीली जमीन पर कमल खिलाने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल और तमिलनाडु का सघन दौरा कर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। दोनों राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक संकेतों से भरा रहा जहां विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के साथ-साथ विपक्ष पर तीखे प्रहार भी किए गए। केरल में प्रधानमंत्री ने राजधानी तिरुवनंतपुरम में भव्य रोड शो से शुरुआत की। केरल में हालिया निकाय चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन और तिरुवनंतपुरम के मेयर पद पर काबिज होने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर गया है। इसी पृष्ठभूमि में मोदी ने रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई और कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। सार्वजनिक सभा में उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि

केरल में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, नयी ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी तमिलनाडु में डीएमके सरकार का काउंटडाउन शुरू - मोदी

विकास और सुशासन के साथ केरल को नई दिशा दी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में सत्तारूढ़ वाम मोर्चे पर निशाना साधते हुए सबरिमला में सोना गायब होने का मुद्दा तो उठाया ही साथ ही उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के संबंधों को लेकर उस पर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि वह राज्य में कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दे रही है। रैली के दौरान एक बच्चे का प्रधानमंत्री का स्केच हाथ में उठाए लंबे समय तक खड़े रहना भी चर्चा का विषय बना। मंच से मोदी का मानवीय संवाद इस दौर

की सहज तस्वीर पेश करता दिखा। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री का रुख अधिक आक्रामक रहा। एनडीए की रैली में उन्होंने सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानि द्रमुक पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, महिला अपमान और तमिल संस्कृति को कमजोर करने के आरोप लगाए। मोदी ने कहा कि सत्ता की यह दल राज्य के मूल्यों और विकास को नुकसान पहुंचा रही है। इसके उलट एनडीए को उन्होंने ईमानदारी, महिला सम्मान और सांस्कृतिक गौरव पर आधारित विकल्प बताया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तमिलनाडु की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का विस्तार से उल्लेख किया। संगम साहित्य, प्राचीन वैज्ञानिक परंपराएं, भव्य मंदिर और आधुनिक तकनीकी योगदान को उन्होंने भारत की सभ्यता की रीढ़ बताया। चेन्नई के निकट चेंगलपट्टु और मदुरांतकम की सभाओं में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य में तमिलनाडु की भूमिका निर्णायक होगी। केंद्र सरकार द्वारा पिछले ग्यारह वर्षों में राज्य के लिए किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की यूपीए सरकारों ने तमिलनाडु को अपेक्षित संसाधन नहीं दिए। मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के शासन की सराहना करते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करने का श्रेय दिया और वर्तमान दौर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। पोंगल के उत्सव और एमजी रामचंद्रन की जयंती का स्मरण कर उन्होंने स्थानीय भावनाओं से जुड़ने की कोशिश की।

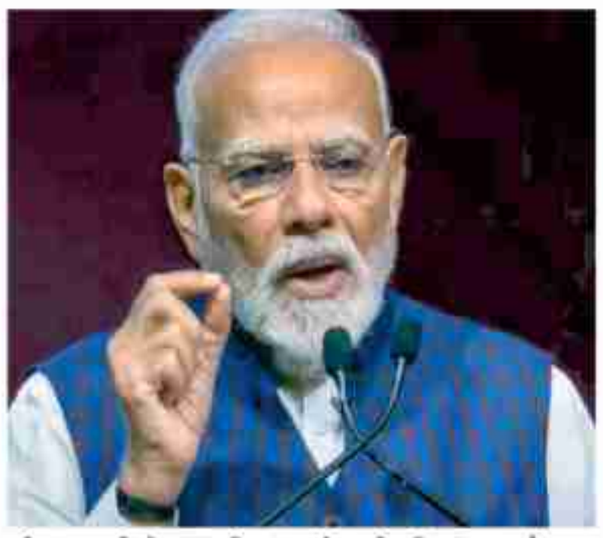

हर मंच से उनका संदेश साफ था कि तमिलनाडु बदलाव के लिए तैयार है। हम आपको यह भी बता दें कि केरल में राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योगपति साबु एम जैकब से मुलाकात की और उनके ट्वेंटी ट्वेंटी संगठन के एनडीए में शामिल होने का स्वागत किया। वर्कला में शिवगिरि मठ और श्री नारायण गुरु परंपरा से जुड़े संतों से भेंट कर उन्होंने सामाजिक समरसता और समानता के संदेश को भी रेखांकित किया। देखा जाये तो दक्षिण भारत लंबे समय से भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहा है। केरल और तमिलनाडु में मजबूत वैचारिक परंपराएं क्षेत्रीय अस्मिता और गठबंधन राजनीति का ऐसा ताना बाना रचती रही है जहां राष्ट्रीय दलों के लिए जगह बनाना आसान नहीं रहा।

ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दोहरा दौरा केवल चुनावी यात्रा नहीं बल्कि रणनीतिक दांव भी है। केरल में हालिया स्थानीय निकाय सफलता ने भाजपा को यह भरोसा दिया है कि संगठन विस्तार और विकास के एजेंडे के सहारे वह अपनी जमीन बढ़ा सकती है। मोदी का रोड शो और सामाजिक संगठनों से संवाद इस बात का संकेत है कि पार्टी केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह समाज के प्रभावशाली वर्गों को साथ जोड़ने की कोशिश में भी है। तमिलनाडु में तस्वीर और भी दिलचस्प है। यहां भाजपा अकेले दम पर नहीं बल्कि सभी विपक्षी दलों को साथ लाकर मजबूत एनडीए के रूप में मैदान में उतरना चाहती है। द्रमुक पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के हमले के साथ-साथ तमिल गौरव का सम्मान नहीं करने का आरोप बताता है कि भाजपा स्थानीय पहचान को साधने की रणनीति अपना रही है। जयललिता और एमजी रामचंद्रन जैसे लोकप्रिय चेहरों का उल्लेख कर मोदी ने उस भावनात्मक खाली जगह को भरने का प्रयास किया है जिसे द्रमुक और अन्नाद्रमुक दशकों से भुनाते रहे हैं। फिर भी यह आसान नहीं है। तमिलनाडु में द्रमुक की मजबूत सांगठनिक पकड़ और केरल में वामपंथी परंपरा भाजपा के सामने बड़ी चुनौती बनी रहेगी। लेकिन मोदी का यह सघन दौरा यह स्पष्ट करता है कि पार्टी अब दक्षिण में हाशिये पर नहीं रहना चाहती। विकास, संस्कृति और सुशासन के त्रिकोण पर आधारित भाजपा का यह अभियान यदि जमीनी स्तर पर संगठनात्मक मजबूती के साथ आगे बढ़ता है तो पथरीली जमीन पर कमल खिलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

राजस्थान-यूपी में बारिश, शिमला-मनाली-श्रीनगर में सीजन की पहली बर्फबारी

नई दिल्ली । उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने से मौसम बदल गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में देर रात से बारिश हो रही है। तेज हवाएं चल रही हैं। कई जिलों में तापमान घट गया है। हिमालय के राज्यों में भी बारिश-बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल के शिमला-मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इससे साढ़े तीन महीने से चल रहा ड्राई स्पेल खत्म हो गया है। जम्मू-कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी जिलों में बर्फबारी जारी है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 इंच तक बर्फ जम गई है, इसके कारण शुक्रवार के लिए सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। श्रीनगर-जम्मू हाईवे भी बंद है। नवयुग टनल के पास ट्रैफिक रोक दिया गया है। मुगल, सिंथन रोड भी बंद हैं। कटरा में बर्फबारी के कारण वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। राजौरी, पुंछ और कठुआ में स्कूल बंद हैं।

उज्जैन के तराना में तनाव, बस फूंकी- दुकान जलाई- मंदिर पर पथराव

सीसीटीवी में युवक पथराव करते-हमला करते दिखे, 13 बसों में तोड़फोड़, 15 गिरफ्तार

उज्जैन । उज्जैन के तराना में शुक्रवार दोपहर एक बार फिर तनावपूर्ण हालात हो गए। गुरुवार रात भी यहां हालात बिगड़े थे। पुलिस बल तैनात है। शुक्रवार दोपहर को जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यह समझ रहे थे कि पूरा मामला शांत हो गया है तभी तकिया मोहल्ला क्षेत्र बस स्टैंड में 50 से 60 लोगों ने जमकर बवाल मचाया। इस दौरान मारपीट और पथराव किए जाने की बात भी सामने आई है। आरोप है कि ये लोग धर्म विशेष के बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि क्षेत्र में दोनों समुदाय के लोग आमने-सामने हो गए थे जिसे तो पुलिस ने रोक दिया, लेकिन इसी बीच किसी व्यक्ति ने यहां खड़ी एक बस में आग लगा दी। बस में आग लगाए जाने की जानकारी जैसे ही लोगों तक पहुंची वैसे ही क्षेत्र में फिर स्थिति बिगड़ गई। तराना क्षेत्र में गुरुवार रात से मचे इस बवाल को अब तक एसडीओपी भविष्य भास्कर, एसडीएम बृजेश सक्सेना, तराना थाना प्रभारी रामनारायण भदौरिया संभाल रहे थे, लेकिन दोपहर को फिर जब बवाल मचा तो एसपी प्रदीप शर्मा तुरंत तराना पहुंच गए और उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। एसपी शर्मा इस दौरान उस क्षेत्र में भी पहुंचे जहां पर बस को जलाया गया था। एसपी अभी तराना में ही है और पूरे मामले पर अपनी निगाह गड़ाए हुए हैं।

मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ अपमान, उप मुख्यमंत्री के आग्रह पर कैसे कर लूं स्नान- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

धरना छठे दिन रहा जारी, तबीयत बिगड़ी

18 जनवरी, मौनी अमावस्या से ही माघ मेले में धरने पर बैठे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तबीयत शुक्रवार को बिगड़ गई। उनको बुखार हो गया है। खुले आसमान के नीचे छह दिन से बैठने के कारण उनकी सेहत बिगड़ गई है। शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने तबीयत खराब होने की पुष्टि की है।

प्रयागराज।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्षमायाचना करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से स्नान करने का आग्रह किया है। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भाजपा में कम से कम ऐसे नेता भी हैं जिन्हें गलती होने पर ग्लानि हुई। उन्होंने क्षमा मांगकर नेक कार्य किया, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि

पूजनीय शंकराचार्य... धरना समाप्त करें... बढ़िया से स्नान करें- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील

मुख्यमंत्री के इशारे पर मेरा अपमान हुआ है। मेरे लोगों को पीटा गया है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री के आग्रह पर कैसे स्नान कर लूं? इस मामले में मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा। मारपीट के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर स्नान करने गया तो पुनः अभद्रता और मारपीट हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सनातन धर्म को कालनेमियों से खतरा होने को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि कालनेमि कौन है उसे वह बेहतर तरीके से जानते हैं। कालनेमियों का चेहरा स्पष्ट है।

यूएस टैरिफ और इकोनॉमी पर बोले राहुल गांधी

45 करोड़+ नौकरियां और लाखों व्यवसाय खतरे में, मोदी जवाबदेह

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो क्लिप साझा की है। राहुल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का जिक्र करते हुए भारत पर हो रहे कथित दुष्प्रभावों को रेखांकित किया है। राहुल ने कहा है कि टैरिफ के कारण देश में करोड़ों नौकरियों के अलावा लाखों व्यवसायी भी खतरे में हैं। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि लोगों को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावी फैसले नहीं लिए। अपने एक्स पोस्ट में राहुल ने हैशटैग- सशक्त्र का भी इस्तेमाल किया है। राहुल की इस टिप्पणी को तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल ने कहा, अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ की मार का उल्लेख करते हुए लिखा, अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया है इससे अनिश्चितता के माहौल में भारत के कपड़ा निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है। कारखाने बंद हो रहे हैं, नौकरियां छिन रही हैं। ऑर्डरों में कमी हमारी बेहाल अर्थव्यवस्था की हकीकत बन चुकी है। उन्होंने ऐसे हालात के लिए पीएम मोदी को जवाबदेह बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहत के लिए प्रभावी कदम न उठाने के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने न तो कोई राहत दी और न ही टैरिफ के बारे में आज तक कोई बयान दिया है। उन्होंने लिखा, 45 करोड़ से अधिक नौकरियां और लाखों व्यवसाय खतरे में हैं। मोदी जी, आप जवाबदेह हैं; कृपया इस मामले पर ध्यान दें!

सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर आजादी के आंदोलन को दी नई दिशा- सीएम योगी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर आजादी के आंदोलन को नयी दिशा दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स पर लिखा, ''भारत माता के सच्चे सपूत, 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' महाघोष के प्रणेता नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर आजादी के आंदोलन को नयी दिशा दी। आपका शौर्य, पराक्रम एवं मां भारती की निस्वार्थ आराधना वंदनीय है। सीएम योगी ने कहा, ''ऐसे महान राष्ट्र आराधक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं प्रदेश वासियों को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद! स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा में हुआ था।

बंगाल में मौत का तांडव! सीएम ममता बनर्जी का दावा

एसआईआर के डर से हर दिन 3-4 लोग कर रहे आत्महत्या

बंगाल । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य में चल रही मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर व्याप्त चिंता के कारण प्रतिदिन तीन से चार लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कोलकाता के रेड रोड स्थित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन मौतों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि 110 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 110 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है; एसआईआर की चिंता के कारण प्रतिदिन तीन से चार लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में मतदाता सूची संशोधन

(एसआईआर) की प्रक्रिया चल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भाजपा पर बंगाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर, बोस और बी आर अंबेडकर जैसे देश के महान व्यक्तित्वों का अपमान किया जा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में, उन्होंने दावा किया कि राज्य में एसआईआर अभ्यास को लेकर तनाव और दहशत के कारण अब तक कम से कम 110 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि एसआईआर अभ्यास के कारण लोगों को झेलनी पड़ रही पीड़ा पर आधारित 26 कविताओं का संकलन उनकी 162वीं पुस्तक इसी मेले में प्रकाशित होगी। बनर्जी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शिविरों में सुनवाई के लिए बुजुर्गों समेत सैकड़ों लोगों को कतार में लगना पड़ता है और उन्हें प्रतिदिन पांच-छह घंटे खुले में इंतजार करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा, तार्किक विसंगतियों का हवाला देते हुए वे (चुनाव आयोग) बंगालियों के उपनामों जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, जो वर्षों से ज्ञात और स्वीकृत हैं।

धार भोजशाला में पूजा के साथ अदा हुई नमाज, पुलिस वाहन में नमाजियों को ले गए भोजशाला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में वसंत पंचमी पर सूर्योदय के साथ ही मां वाग्देवी का पूजन शुरू हो गया है। सुबह वेदारंभ संस्कार के साथ ही इसकी शुरुआत हुई। वहीं, दोपहर में परिसर में एक बजे से मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करना भी शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह स्पष्ट है कि दोनों समुदाय के आयोजन अलग-अलग स्थानों पर हो रहे हैं। पूजा-अर्चना निर्विघ्न होगी। मुस्लिम समाज को अलग स्थान दिया गया है। ऐसे स्थान की तलाश में प्रशासन ने स्वयं सर्वे किया है। मध्य प्रदेश के धार जिला स्थित भोजशाला में शुक्रवार दोपहर 1.30 बजे पुलिस कुछ नमाजियों को लेकर भोजशाला परिसर पहुंची। भोजशाला के मुख्य द्वार के पास कमाल मौला दरगाह की और जाने वाले रास्ते से उन्हें भीतर ले जाया गया। कुछ देर में नमाजियों ने नमाज अदा की। इसके तुरंत बाद

कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पुलिस वाहन में ही परिसर से बाहर ले जाया गया। इधर भोजशाला परिसर में इस दौरान पूजन-दर्शन का क्रम भी जारी रहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से भी नक्शा लिया है। दोनों पक्षों की बैठक बुलाई गई और इस व्यवस्था से हिंदू समाज संतुष्ट है। मुस्लिम समाज से भी चर्चा हुई है और उन्हें विकल्प दिए गए हैं। यदि यह पक्ष राजी नहीं होता है तो प्रशासन फैसला लेगा। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने स्पष्ट किया कि हिंदू समाज पूर्व परंपरा के अनुसार पूजन करेगा। कलेक्टर के अनुसार, कोर्ट का कहना है कि प्रवेश-निकासी अलग होनी चाहिए। परिसर में और भी जगह है। जिला प्रशासन कानून व्यवस्था को देखते हुए स्वयं से स्थान तय कर सकता है। यदि यह स्थान सहमति के आधार पर तय होता, तो ठीक है। यदि सहमति नहीं बनती है तो स्थानीय प्रशासन स्थान तय कर सकता है। वहीं, इससे पहले भोजशाला मुक्ति यज्ञ के पदाधिकारियों की ओर से कहा गया कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा शांतिपूर्ण और निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी।

पुलिस-प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था

करीब 8000 पुलिसकर्मी जिले में तैनात किए गए हैं। इनमें 1000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी हैं। 13 आईपीएस अधिकारी सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं। 25 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 107 नगर निरीक्षक व उप निरीक्षक, 393 अन्य अधिकारी-कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। भोजशाला के आसपास 300 मीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। 1000 सीसीटीवी कैमरे शहर और भोजशाला परिसर में लगाए हैं। 20 ड्रोन कैमरों और एआइ तकनीक से निगरानी की जा रही है। 350 से अधिक पुलिस कर्मियों को भोजशाला के भीतर और 100 पुलिस कर्मियों को छत पर तैनात किया गया है। थ्रीडी मैपिंग सहित आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है।

सीएम स्टालिन की केंद्र को सीधी चुनौती, मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित

नई दिल्ली । तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव को पारित कर केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध किया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि वह ग्रामीण रोजगार योजना के लिए महात्मा गांधी का नाम बरकरार रखे और वास्तविक रोजगार मांग और राज्य सरकार प्रदर्शन के अनुरूप पर्याप्त और निरंतर निधि आवंटन सुनिश्चित करे। इसमें ग्रामीण नागरिकों के काम के अधिकार की रक्षा पर बल दिया गया और कार्यक्रम के महत्व को महिलाओं, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उजागर किया गया, जिन्हें प्राथमिक लाभार्थी बताया गया। इसमें केंद्र सरकार की मौजूदा मनमानी से, काल्पनिक अनुमानों के आधार पर निधि आवंटन की प्रथा की आलोचना की गई और उस पूर्व प्रणाली पर लौटने की मांग की गई जिसमें काम की वास्तविक मांग के आधार पर निधि

जारी की जाती थी। प्रस्ताव में राज्य सरकार के योगदान को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्तावित कदम पर भी आपत्ति जताई गई, जिसे विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के तहत नामित किया गया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि ऐसा कदम राज्य के वित्त पर भारी दबाव डालेगा और ग्रामीण आजीविका को नुकसान पहुंचाएगा। इस सप्ताह विधानसभा में राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण रहा, जिसके चलते प्रस्ताव पारित हुआ। सदन में इस वर्ष के पहले सत्र के दौरान पहले ही काफी हंगामा हो चुका था, जब राज्यपाल आर.एन. रवि ने डीएमके सरकार द्वारा तैयार किए गए पाठ को गलतियों का हवाला देते हुए पढ़ने से इनकार कर दिया और सदन से बाहर चले गए। स्टालिन ने राज्यपाल पर संवैधानिक प्रावधानों और विधायी परंपराओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया और कहा कि यदि ऐसी घटनाएं जारी रहीं तो डीएमके संसद में संवैधानिक संशोधन लाने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से परामर्श करेगी।